"समानता का अधिकार ही प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीय एकता का मूलमन्त्र है"

- गजेन्द्र नारायण सिंह

नेपाल सद्भावना पार्टी
का
चुनाव घोषणा पत्र
२०४८

"पंजा"

चुनाव चिन्ह

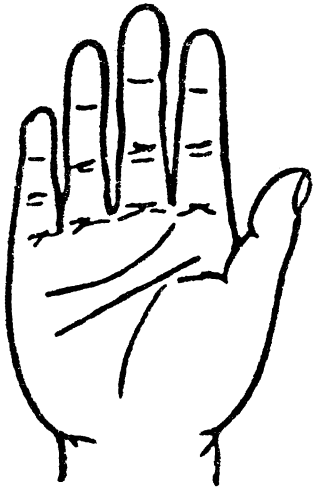

"वन विनाश रोकेंगे-देशको समृद्ध बनाएंगे
भेदभाव मिटाएंगे- सद्भावना बढाएंगे"

- प्रस्तावना -

नेपाल एक बहुभाषी देश है । यहां अनेक जातीय समुदाय तथा जनजातियां निवास करती हैं । "जातीय असन्तुलन" तथा "भेदभावपूर्ण नीतियों एवं व्यवहारों" के कारण नेपाल के बहुसंख्यक समाज को आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषायी भेदभाव आदि अनेक प्रकार के शोषणों एवं उत्पीड़नों का शिकार होना पड़ रहा है । इससे आपसी सद्भाव में तो कमी आयी ही है, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तथा गति में भी शिथिलता आयी है । सं. २०४० में जनसंख्या आयोग के तत्वावधान में गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत बसाई-सराई प्रतिवेदन शासक वर्ग की भेदभावपूर्ण मनःस्थिति का प्रामाणिक उदाहरण था । इसी प्रतिवेदन में मधेशियों को नागरिकता से वंचित करने, नेपाल-भारत खुली सीमा को बन्द कर देने, तराई की भाषा एवं संस्कृति को नष्टकर मधेशियों की पहचान सदा-सदा के लिए मिटाने जैसे, मधेश एवं मधेशी-हितविरोधी अनेक सुझाव दिए गए थे । फलस्वरूप मधेशी समुदाय आतंकित हो उठा । चारो ओर आपसी मनमुटाव एवं अविश्वास का वातावरण छा गया । तराई क्षेत्र को आतंकित एवं आशंकित करनेवाला "बसाई-सराई प्रतिवेदन" तत्कालीन शासक पक्ष के दिमाग की खुराफात तो थी ही, साथ ही यह आश्चर्य एवं दुख का विषय तब बन गया जब तत्कालीन विपक्षी प्रतिबंधित राजनीतिक दलों (वर्तमान सत्तापक्ष) एवं उनके नेताओं ने राष्ट्रीय एकता पर प्रश्नचिह्न लगानेवाले इस प्रतिवेदन का खुल्लमखुल्ला समर्थन किया । "प्रजातंत्र के इन स्वयंघोषी मसीहों" ने इस प्रतिवेदन का समर्थनकर अपने को कुछ "जाति-विशेष-समुदाय" के पक्षधर के रूप में खुलकर खड़ा कर दिया । अतः देश में, खासकर तराई में फैल रही दुर्भावना एवं अविश्वास के घातक जहर को हटाकर, आपसी विश्वास एवं सद्भाव का वातावरण बनाने के लिए तत्काल "नेपाल सद्भावना परिषद" नामक एक समाजसेवी संगठन की स्थापना की गई । तब से नेपाल

सद्भावना परिषद, नेपाल की आधी से अधिक जनसंख्यावाले मधेशियों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष करती रही । बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्ति के संघर्ष में नेपाल सद्भावना परिषद ने पूरी शक्ति से भाग लिया । परिषद के अनेक नेता एवं कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए और यातनाओं एवं दमन के शिकार हुए । बहुदलीय प्रजातंत्र की बहाली के बाद नेपाल सद्भावना परिषद को राजनीतिक दल के रूप में गठित किया गया और नेपाल सद्भावना पार्टी नाम रखा गया । "नेपाल सद्भावना पार्टी आज सर्वप्रथम जन-आन्दोलन में अपने प्राणों की आहुति दे चुके ज्ञात-अज्ञात शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है ।"

नेपाल सद्भावना पार्टी बहुदलीय प्रजातांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ और समृद्ध करने तथा देश में किए जा रहे सभी प्रकार के "भेदभावों" एवं "शोषणों" को मिटाने के लिए संघर्ष करते हुए समतावादी समाज की स्थापना के द्वारा देश के सभी जातीय समुदायों एवं जनजातियों की भाषा, वेश-भूषा एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखकर, नेपाल को एक विकसित एवं समुन्नत राष्ट्र बनाने के ऐतिहासिक दायित्व को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है । नेपाल सद्भावना पार्टी सभी प्रकार के भेदभावों एवं शोषणों को समाप्तकर, स्वतंत्रता, समता, न्याय एवं सद्भावना के ऐसे युग का सूत्रपात करना चाहती है जिसमें देश की अखंड भौगोलिक सीमा के अन्दर रहनेवाली सभी वर्ग, समुदाय एवं जनजातियां अपने को राष्ट्र की मूलधारा में आबद्ध एवं पोषित महसूस करें ।

नेपाल सद्भावना पार्टी नेपाली समाज पर किसी जाति, वर्ग या समुदाय विशेष के वर्चस्व को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी । लेकिन, यह पार्टी किसी भी वर्ग, जाति या समुदाय विशेष का विरोधी नहीं है । यह तो शोषण के विरुद्ध संघर्ष करनेवाली एक पार्टी मात्र ही नहीं, बल्कि आन्दोलन है । वस्तुतः नेपाल सद्भावना पार्टी प्रत्येक देशवासी के लिए सम्मानपूर्ण जीवन-यापन हेतु उपयुक्त आधार एवं वातावरण का निर्माण करना चाहती है । संक्षेप में आर्थिक, राजनीतिक,

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषागत भेदभाव तथा शोषण को समाप्तकर एक सुदृढ़ समतावादी एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण करना नेपाल सद्भावना पार्टी का मुख्य उद्देश्य है । इस पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यक कार्यक्रम एवं नीतियों के तहत संघर्ष को निरन्तरता प्रदान करने के साथ ही नेपाल सद्भावना पार्टी आगामी निर्वाचन में सहभागी होकर देशवासियों के सम्मुख निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का संकल्प लेती है :-

१. **संघीय सरकारः** नेपाल एक बहुभाषी, बहु-सामुदायिक एवं अनेक जनजातियों का देश होने के कारण राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने एवं प्रशासन में सन्तुलित भागीदारी के लिए नेपाल सद्भावना पार्टी देश में संघीय सरकार की संवैधानिक व्यवस्था को उपयुक्त मानती है । यह पार्टी भाषा, वेश-भूषा, संस्कृति एवं भौगोलिक एकरूपता के आधार पर पर्वत-पहाड़ों सहित तराई को भी एक इकाई मानकर, स्वायत्त प्रान्त घोषित करने का पक्षधर है । ताकि, प्रान्तीय स्तर पर शासन और प्रशासन में पर्वत एवं पहाड़ी क्षेत्रों की बहुसंख्यक उपेक्षित जातियों एवं तराई के मधेशी समुदाय की समुचित भागीदारी से उनकी भाषा, वेश-भूषा तथा संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास सुनिश्चित हो सके ।

२. **मौलिक हक एवं अधिकार :** यह पार्टी संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं अधिकारों को कुंठित करनेवाले प्रतिबन्धतात्मक वाक्यांशों को संविधान से हटाकर, मानव अधिकारों को पूर्णयता संरक्षण प्रदान करने को कृतसंकल्प है ।

३. **न्याय सुधार :** यह पार्टी शक्ति विभाजन के सिद्धान्त अनुरूप जनता के मौलिक हक के संरक्षण के लिए न्यायपालिका के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हुए इसे राज्य के अन्य अंगो के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त रखने का पक्षधर है । यह पार्टी गरीब, निर्बल एवं असहाय पक्ष के लिए निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा

उपलब्ध कराएगी । साथ ही सुलभ एवं समय पर न्याय दिलाने की व्यवस्था भी करेगी ।

४. **धार्मिक स्वतंत्रता :** यह पार्टी देश के सभी धर्मों का समान भाव से आदर करती है और धर्म को निजी आस्था का विषय मानती है । इसलिए पार्टी, धर्म को राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने का पक्षधर है ।

५. **आर्थिक नीति :** यह पार्टी देश के द्रुततम आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढाँचे को अपनाएगी तथा राष्ट्रीय राजस्व का, देश के हर इलाके के लिए न्यायोचित ढंग से समानुपातिक आबंटन करेगी । पार्टी मानती है कि भेदभावपूर्ण, अव्यावहारिक एवं असमान कर प्रणाली के तहत करदाताओं पर दोहरी-तेहरी कर का बोझ लादना अन्याय है । इसलिए कर-प्रणाली को व्यावहारिक, न्यायसंगत एवं प्रगतिशील बनाया जाएगा ।

६. **कृषि नीति :** नेपाल एक कृषि प्रधान देश है । अतः कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से "हर हाथ को काम- हर खेत को पानी" के नारा को चरितार्थ करने के लिए यह पार्टी-

- देश में चकबन्दी-व्यवस्था करेगी ।
- मोही के हक एवं हितों को सुरक्षित रखते हुए दोहरे स्वामित्व प्रथा को समाप्त करेगी ।
- चार बिघा तक के जोत को "अलाभकारी-जोत" घोषितकर उसे लगान-मुक्त घोषित करेगी ।
- कृषि क्षेत्र को भी औद्योगिक क्षेत्र घोषितकर, उसे उद्योगों को मिलनेवाली आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या कराएगी ।
- कृषि मजदूरों को बेहतर "मजदूरी" एवं "सुविधाएँ" उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कारगर कदम उठाएगी ।
- कृषि कार्य हेतु लिए गए कर्जों का, मूलधन से अधिक ब्याज वसूली पर रोक लगाएगी एवं

प्रचलित "सामन्ती-ब्याज दर" को कमकर न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी ।

- चार बिघे तक की जोतवालों को कृषि सामग्री की खरीद के लिए बिना जमानत ऋण दिलाने की व्यवस्था करेगी ।
- "कृषि पर आयी लागत" एवं तदनुसार होनेवाले "उत्पादन" को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सन्तुलन कायम करने के लिए, फसल तैयार होने से पूर्व ही कृषि मूल्य निर्धारण कर "सरकारी-खरीद" की व्यवस्था करेगी ।
- छोटे किसानों की स्थिति सुधारने के लिए चार बिघे से कम जोतवाले कृषकों को कृषि सामग्री एवं यन्त्रों की कीमतों में सहुलियत (छूट) देने की व्यवस्था करेगी ।
- पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन एवं फल-फूल की खेती को विकास के लिए रियायती ब्याज-दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारेगी ।
- सिंचाई प्रणाली का समुचित विकास करेगी ।
- खाद तथा उन्नत एवं प्रशोधित बीज, न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराएगी ।
- ट्रैक्टर पम्पिंग सेट तथा अन्य कृषि संयंत्रों पर "भन्सार" एवं "अन्य करों" में विशेष छूट-सुविधा की व्यवस्था करेगी ।

७. **औद्योगिक नीति** : देश को क्रमशः आत्मनिर्भर बनाने हेतु निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों के विकास के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देगी । छोटे एवं घरेलू उद्योगों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था करेगी । उद्योगपतियों एवं श्रमिकों के बीच उत्पन्न विवादों की त्रिपक्षीय सम्झौता-वार्ताओं के द्वारा समाधान करेगी । सुस्पष्ट प्रगतिवादी उद्योग नीति को स्थायित्व प्रदान करेगी ।

८. **सामाजिक नीति** : समाज में व्याप्त विकृति, अन्धविश्वास एवं कुरीतियों को निर्मूलकर प्रगतिशील समाज का निर्माण करेगी । पुरातात्विक ., धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के मन्दिर, मस्जिद, मठ, गुरूद्वारा, विहार, गिरिजाघर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सम्मानपूर्वक संरक्षण एवं सम्वर्द्धन करेगी । सामाजिक रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए होली, दिवाली, छठ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, वार-वफात (मुहम्मद जयन्ती) जैसे सभी धर्मो के प्रमुख त्योहारों के अवसरों पर सार्वजनिक राष्ट्रीय अवकाश घोषितकर सभी धर्मों के रीति-रिवाजों, परम्पराओं, एवं संस्कृतियों को मैत्रीपूर्ण ढंग से विकसित होने के लिए प्रोत्साहन देगी तथा सभी धर्मों की सामाजिक मान्यताओं का सम्मानकर सभी नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत कराने के कार्य को प्राथमिकता देगी । असहाय वृद्ध-वृद्धा एवं अबला महिलाओं को "असहाय - भत्ता" मुहैय्या कराने की व्यवस्था करेगी ।

९. **निर्वाचन क्षेत्र** : समान जनसंख्या तथा भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर ही तराई और पहाड़ में निर्वाचन क्षेत्र कायम करने के लिए पार्टी कृतसंकल्प है ताकि समानुपातिक आधार पर जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन सम्भव हो सके ।

१०. **आरक्षण नीति** : कुछ "जातिविशेष" के लिए "अघोषित आरक्षण की नीति" को समाप्त कर केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों तथा उसके अन्तर्गत की सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी सेवाओं सहित, संस्थानों, की सेवा के अवसरों में जनसंख्या के आधार पर उपेक्षित जनजातियों एवं जातीय समुदायों को "समानुपातिक आरक्षण" देने के लिए पार्टी वचनवद्ध है । सदियों से उपेक्षित-अवहेलित एवं शोषित देश की आधी से अधिक जनसंख्यावाले मधेशियों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व को

सुनिश्चित करने के लिए मधेशियों को "पचास प्रतिशत आरक्षण" देने हेतु नेपाल सद्भावना पार्टी कृतसंकल्प है ।

११. **नारी समस्या** : हमारे समाज में नारी का शोषण और उत्पीड़न जारी है । यह पार्टी इसे रोकने और महिलाओं को शिक्षित-दीक्षितकर शासन-प्रशासन में उनकी समुचित सहभागिता की व्यवस्था करने का समर्थक है । महिलाओं की कार्यदक्षता को बढ़ाने और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए पार्टी नारी समाज के साथ हो रहे सभी प्रकार के शोषण, अत्याचार एवं भेदभाव का पूरी तरह अन्त कराएगी ।

१२. **शिक्षा नीति** :

- प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिलाने के साथ ही दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी । पिछड़ी जातियों, खासकर हरिजनों के लिए उच्च शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क करने तथा उनके लिए विशेष छात्रवृति की व्यवस्था करेगी । साथ ही प्राथमिक पाठशालाओं की भांति संस्कृत पाठशालाओं एवं मदरसों को भी राजकीय संरक्षण प्रदान करेगी ।
- व्यावसायिक शिक्षा नीति का अवलम्बन करेगी ।
- विगत कई वर्षों से कार्यरत अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को स्थायी करवाने तथा शिक्षकों के वेतनमान को सुदृढ़कर उन्हें यथासंभव सुविधा प्रदान करेगी ताकि उनका जीवनस्तर उंचा उठ सके और वे सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें ।
- देश में शिक्षालय के असन्तुलन को हटाने के लिए राजर्षि जनक एवं महात्मा बुद्ध के नाम से क्रमशः विराटनगर और लुम्बिनी में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी और जनकपुर तथा नेपालगंज में एक-एक मेडिकल कालेज की स्थापना करेगी । वीरगंज में एक इंजीनियरिंग कालेज तथा

राजविराज में "पोलिटेक्निक इंस्टीच्यूट" स्थापित करेगी ।

१३. **परराष्ट्र नीति :** यह पार्टी विश्व के सभी देशों से समानता के आधार पर मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का पक्षधर है । इसके साथ ही महान् प्रजातन्त्रवादी पड़ोसी राष्ट्र भारत के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध अद्वितीय रहने तथा दोनों देशों की सीमाएं "खुली रहने के कारण" सुरक्षा की दृष्टि से भी दोनों देशों के इस स्वाभाविक घनिष्ठ सम्बन्ध को मजबूत बनाने और एकसाथ क्रियाशील बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है । अतः यह पार्टी भारत के साथ "अटूट विशेष सम्बन्ध" कायम रखने का पक्षधर है ।

१४. **प्रतिरक्षा :** यह पार्टी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेना में विशेष वर्ग एवं समुदायों के लोगों के "अघोषित प्रवेश निषेध" को समाप्तकर, देश के सभी भाषा-भाषियों, जातियों, जनजातियों एवं समुदायों को आवश्यक रूप से प्रवेश के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करेगी तथा मातृभूमि की सुरक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र से आज तक वंचित "मधेशियों" की एक अलग बटालियन खड़ा कराएगी ताकि मातृभूमि की रक्षा जैसे पवित्र कार्य से किसी भी भाषा-भाषी, जाति, जनजाति एवं समुदाय विशेष के लोग वंचित न रहें और देश प्रेम की भावना सभी देशवासियों में समान रूप से निरन्तर बढ़ती रहे । उल्लेखनीय है कि देश की सुरक्षा के लिए गठित सेना, साहस-हिम्मत का आदर्श प्रस्तुत करती है जिसमें देश की आधी से अधिक आवादीवाले मधेशी प्रवेश पाने से अभी भी वंचित हैं ।

१५. **संचार नीति :** सरकारी संचार माध्यमों-रेडियो नेपाल, नेपाल टी.वी. आदि द्वारा नेपाली और हिन्दी के अतिरिक्त विभिन्न मातृभाषाओं में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत कराने की व्यवस्था करेगी और साथ ही सम्बन्धित भाषाओं में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन कार्य को प्रोत्साहन देगी । यह

पार्टी सम्पूर्ण संचार माध्यमों को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं मर्यादित रखने के उद्देश्य से उन्हें स्वायत्त इकाई में परिणत करने के पक्ष में है।

१६. **यातायात नीति** : यह पार्टी देश में सड़कों का जाल बिछाकर यातायात सुविधा सुलभ कराएगी। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से पूर्व में मेची और पश्चिम में महाकाली तक रेलमार्ग का निर्माण कराएगी। देश के आपार जलस्रोत द्वारा विद्युत उत्पादन बढाकर मोटरों एवं रेलगाड़ियों को विद्युत द्वारा संचालित कर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगी।

१७. **जलस्रोत** : जलस्रोत, नेपाल के लिए "तरल-स्वर्ण" जैसा बहुमूल्य साधन है। ने.स.पा. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों से जलस्रोत का प्रयोगकर, उसके बहुमुखी उपयोग के पक्ष में है। बहुमुखी उपयोग का तात्पर्य सिंचाई, जल-विद्युत उत्पादन तथा जल-यातायात से है।

१८. **नागरिकता**: वर्तमान संविधान के घोषणा होने के दिन तक नेपाली भूमि पर स्थायी रूप से बसोवास करनेवाले प्रत्येक देशवासी को नेपाल की नागरिकता का प्रमाणपत्र दिलाने को पार्टी "कृतसंकल्प" है। यह पार्टी इस कार्य की सुगमता के लिए २०३६ साल में सम्पन्न जनमत संग्रह के मतदाता नामावली को भी एक आधार के रूप में मानती है।

१९. **भाषा**: ने.स.पा. नेपाली और हिन्दी के अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ऊर्दू, थारू, राजवंशी, नेवारी, उरांव, सतार, तामांग, राई, लिम्बू, मगर, गुरूंग, मारवाड़ी आदि भाषा सहित देश के अन्य सभी "सम्पन्न राष्ट्रभाषाओं" के विकास के लिए, उन्हें संविधान में सूचीवद्धकर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा विकसित मातृभाषाओं में प्रदान करने की व्यवस्था को राजकीय जिम्मेवारी मानती है। साथ ही नेपाली भाषा के समकक्ष ही "सम्पूर्ण तराई की परम्परागत पठन-पाठन की भाषा एवं तराई और पहाड़ों के बीच सम्पर्क

भाषा -"हिन्दी" को "राष्ट्र भाषा" का दर्जा दिलाने का पक्षधर है ।

२०. **पर्यावरण एवं पुनर्वास :** वन जंगलों की अनियंत्रित कटाई कर, एक समुदाय विशेष के लोगों को ही तराई क्षेत्र में सुकुमवासी (भूमिहीन अथवा विस्थापित) के नाम पर षड्यन्त्रपूर्ण ढंग से जमीन मुहैय्या कराए जाने की वजह- "तराई में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असन्तुलन" पैदा हुई तथा "तराई क्षेत्र में आदिकाल से निवास कर रहे लोगों का तीव्र दोहन हुआ है । अतः ने.स.पा. पहाड़ों में फल-फूल एवं कुटीर उद्योगों का द्रुत गति से विकास करेगी तथा उसे यातायात की दृष्टि से सुगम बनाकर पहाड़ से तराई की ओर जनसंख्या पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वातावरण तैयार करेगी । साथ ही मधेशी भूमिहीनों को खेती योग्य भूमि वितरणकर समान सामाजिक न्याय कायम करेगी । "वन बचाएं -देश बचाएं" के नारा को बुलन्द करते हुए भविष्य में वन विनाश को पूर्णतः रोककर प्राकृतिक संतुलन कायम करेगी ।

२१. **स्वास्थ्य नीति :** जन सामान्य को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की नीति को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास एवं विस्तार किया जाएगा । जनसंख्या की दृष्टि से सघन क्षेत्र पूर्वी नेपाल के "राजविराज" एवं पश्चिमी नेपाल के "परासी" में पचास-पचास शैय्यावाले आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न अस्पतालों का निर्माण कराएगी ताकि पूर्वी और पश्चिमी नेपाल की सघन आवादी को स्वास्थोपचार के लिए सुदूरवर्ती स्थानों तक नहीं जाना पड़े । इसके साथ ही जिला अस्पतालों को भी स्वास्थ्योपचार के लिए पूर्णतः सक्षम बनायेगी ।

२२. **विकास क्षेत्रों का पुनर्गठन :** यह पार्टी मानती है कि अंचल जैसा ही, विकास क्षेत्रों का पंचायतकालीन विभाजन, भेदभाव का पोषक,

षड्यन्त्रपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है । अतः यह पार्टी समान जनसंख्या तथा मौंगोलिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर विकासक्षेत्रों का पुनर्गठन कर उसी आधार पर राष्ट्रीय सभा में सदस्य चुने जाने का पक्षधर है ।

२३. **ग्राम विकास नीति :** गांवों को "विकास की प्राथमिक इकाई मानकर विकास का लाभ सच्चे अर्थ में ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक गांव को स्वच्छ पेयजल, सदरमुकाम से जोड़ने वाली "सम्पर्क - सड़कों" का निर्माण, तेजी से ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण बाजार व्यवस्था, पाठशाला एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माणकर ग्रामीण एवं शहरी जीवन स्तर के बीच निरन्तर बढ़ती खाइयों को क्रमशः समाप्त करेगी । ग्रामीण महिलाओं के लिए "सुलभ शौचालयों" का जाल बिछाना पार्टी के कार्यक्रम का मुख्य अंग है। ताकि, महिला स्वास्थ्य स्थिति बेहतर हो सके ।

२४. **नगर विकास नीति :** शहरी जीवन को स्वच्छ, स्वास्थकर एवं "प्रदूषण-विहीन" बनाने हेतु बहुमुखी नगर विकास योजना को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा । नगर विकास के नाम पर "बलपूर्वक" एवं "भेदभावपूर्ण" ढंग से भूमि अधिग्रहण करने की प्रवृत्ति को पूर्णतः रोककर, स्थानीय जनता की इच्छा एवं सहमति से ही-जमीन अधिग्रहण द्वारा नगर विकास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी । नगर विकास की योजना बनाते समय "पर्यावरण-सुरक्षा" एवं "वातावरणीय संतुलन" को ध्यान में रखा जाएगा । खासकर नदियों को गंदेनाले के रूप में परिवर्त्तित होने से बचाया जाएगा ।

२५. **बेरोजगारी :** ने.स.पा बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए "बेरोजगार सेल" का गठनकर, देश भर के शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजागरों की सही संख्या का पता लगाएगी तथा योग्यता, कार्यशीलता एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए

प्रयासरत रहेगी । "शिक्षित बेरोजगारी भत्ता" की व्यवस्था करेगी । ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिलाने को उच्च प्राथमिकता देगी । परन्तु, इससे भी ऊपर नेपाल सद्भावना पार्टी "रोजगार पाने के हक" को संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ने के पक्ष में है ।

२६. **श्रम नीति :** सरकारी सेवकों एवं संस्थान, बैंक, बीमा कम्पनी आदि के कर्मचारियों के वेतनमान में सामयिक परिवर्त्तनों के सम्बन्ध में पार्टी अपनी स्थापना के समय से ही सचेष्ट रही है । महंगाई एवं राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार वेतनमानों में वृद्धि का, यह पार्टी समर्थक रही है । कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यमान बाधाएं, विकृतियां एवं शोषण आदि को हटाकर आधुनिक ढंग से उत्पादन वृद्धि कार्य में पार्टी की पूर्ण सहयोगात्मक भूमिका रहेगी । उद्योगपतियों एवं मजदूरों के बीच का आपसी विवाद त्रिपक्षीय समझौता-वार्ता द्वारा समाधान करने के लिए पार्टी सदा तत्पर रहेगी । प्रबंधन, मजदूर संगठन एवं सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढ़ेंगे । देश के माथे पर कलंक के रूप में विद्यमान "बंधुआ मजदूर" एवं "कमैया-प्रथा" का उन्मूलन करने के लिए पार्टी कृतसंकल्प है ।

२७. **ईंधन नीति :** आज एक ओर तराई की अमूल्य वन-सम्पदा का विनाश किया जा रहा है तो दूसरी ओर वहीं के निवासियों को ईंधन के लिए उपलों (गोबर) और "स्वरपतवार" पर निर्भर रहना पड़ रहा है । अतः ग्रामीण इलाकों में सुविधापूर्ण स्थान पर ईंधन-डिपो स्थापितकर जलावन एवं घर बनाने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी । साथ ही, ऊर्जा के घरेलू स्रोत "गोबर" एवं "मानव-मल" से गैस ईंधन तैयार करने की विकासशील देश की प्रविधि

अपनाने पर भी जोर दिया जाएगा । ताकि, खेतों के लिए "मल-स्वाद" भी आसानी से उपलब्ध हो सके ।

२८. **राष्ट्रीय जनगणना** : विकसित शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग जनगणना भी है जिसके माध्यम से राज्य की जनशक्ति की यथार्थ स्थिति की जानकारी सरकार एवं समाज को होती है । जनसंख्या की सही स्थिति की जानकारी होने पर ही नीति निर्माण करना सरल होता है । लेकिन, "राजनीतिक षड्यन्त्र" के तहत नेपाल की जनसंख्या गलत ढंग से "एक करोड़ अस्सी लाख" अथवा इससे भी अधिक होने के दावे देश-विदेशों में किए जाते रहे हैं । २०१८ साल तदनुसार १९६२ ई. के बाद २५ लाख से अधिक लोग पहाड़ से तराई में आकर बस गए हैं । उनके नामों का उल्लेख अनेक स्थानों पर होने से ही जनसंख्या इतनी अधिक दीखती है । यह स्थिति लगभग हरएक क्षेत्र में है । इसलिए ने.स.पा. एक निष्पक्ष आयोग के द्वारा, जिसमें सभी जाति, धर्म सम्प्रदाय एवं क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व रहेगा, देश में जनगणना कराकर, विभिन्न भाषाभाषी , जात-जातियों एवं धर्मावलम्बियों आदि की सही संख्या का पता लगाएगी । ताकि, हर क्षेत्र में उनकी समानुपातिक भागीदारी के प्रतिशत सुनिश्चित करने तथा समानता का हक देने-दिलाने में भी असानी हो ।

२९. **लापता राजबन्दी एवं राजनीतिक बन्दियों की रिहाई** : प्रजातंत्र स्थापना के संघर्ष के दौरान लापता कर दिए गए डा. लक्ष्मी नारायण झा, साकेत चन्द्र मिश्र, दिलीप चौधरी, ईश्वर लामा, सूर्यनाथ राय (यादव), महेश चौलागाईं, पद्म लामा आदि के "मृत" अथवा "जीवित" अस्तित्व के बारे में प्रमाणिक तथ्यों का पता लगाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाएगा और यथार्थ की जानकारी जन-समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत की जाएगी । इन घटनाओं

के लिए दोषी अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी । अन्तरिम सरकार के निकम्मेपन के कारण अभी तक अनेक राजबन्दी कारागार में सड़ रहे हैं, पार्टी उन्हें ससम्मान रिहा कराएगी । साथ ही भावी पीढ़ी को प्रेरणा देते रहने के लिए निष्पक्ष भाव से हर क्षेत्र के अमर शहीदों की प्रतिमाओं की स्थापना, सम्बंधित क्षेत्रों में कराएगी ।

श्रद्धेय माईयों एवं बहनों,

आपको मालूम है कि उक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नेपाल सद्भावना पार्टी लम्बे अर्से से निरन्तर संघर्ष करती आ रही है । ने.स.पा. अपने खिलाफ अनेक सरकारी षड्यन्त्रों, लाठियां-पथरावों और गिरफ्तारियों की कार्रवाई का साहस के साथ सामना कर रही है । मानव सभ्यता के इस मोड़ पर "जातीय" और "क्षेत्रीय भेदभाव" एवं "शोषण" हमारी मातृभूमि के माथे पर लगाया गया कलंक का टीका है । इस काले धब्बे को मिटाने के लिए ने.स.पा. हर तरह के दुःख और कष्ट सहने को तैयार है । ने.स.पा. को विश्वास था कि बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना के बाद सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में सत्ता की कुर्सी पर आसीन नेपाली काँग्रेस एवं कम्युनिस्टों द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे लेकिन इस उम्मीद के विपरीत वर्तमान अन्तरिम सरकार ने कई "मधेशी-विरोधी" कदम उठाकर अपने को सिर्फ "एक समुदाय विशेष" का ही प्रतिनिधि साबित किया है । अतः "समानता का अधिकार प्राप्ति" की यह "पवित्र लड़ाई" है जिसमें आज हमारी मातृभूमि का हर मतदाता साहस और ईमानदारी के साथ शामिल हो रहा है । अब वक्त आ गया है सड़क-खेत-खलिहानों की लड़ाई को, प्रतिनिधि सभा की चुनाव की लड़ाई से जोड़ने का । हमारे विरोधी बड़े षड्यन्त्रकारी और "सत्ता-साधन-सम्पन्न" हैं । मगर हमारे भी इरादे पक्के और उद्देश्य नेक हैं । सत्य हमारे पक्ष में है । विवेक और साहस के साथ लड़ने से सत्य की विजय होगी ।

आज प्रत्येक देशभक्त भेदभाव एवं शोषण के खिलाफ इस लड़ाई के अग्रिम योद्धा है। इतिहास ने इस चुनावी लड़ाई का भार आपके कंधों पर सौंपा है, विशेषकर छात्रों एवं नौजवानों के सहयोग के बिना "समानता" तथा "सम्मान का जीवन जीने के लिए अधिकार पाने" की यह लड़ाई सफल नहीं हो सकती। इसलिए पार्टी का क्रान्तिकारी आह्वान है कि आप कमर-कसकर इस चुनावी संघर्ष में सक्रिए हों। हमारी "अगली पीढ़ी" मानवाधिकार के लिए इस ईमान्दार लड़ाई के नतीजे का बेसब्री से इन्तजार कर रही है। आप उन्हें मायूस न करें। उन्हें भेदभाव की चक्की में पिसने से बचाएं। अन्यथा, इतिहास और भावी पीढ़ी इस वर्तमान को धिक्कारेगी।

अब निर्णय आपके हाथ में है -

निर्णय करे आपका हाथ, आपका है यह पंजा छाप।
पंजा छाप पर मोहर लगाएं, समानता का अधिकार पाएं॥

नेपाल सद्भावना पार्टी के हाथ के पंजे पर लगी एक मोहर, आपकी जीत की छाप छोड़ेगी।

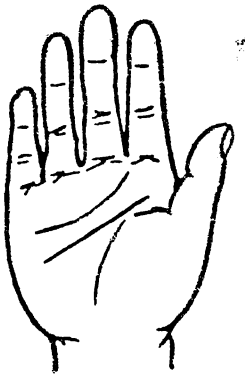

"पंजा"
चुनाव चिन्ह

"जय मातृभूमि"

नेपाल सद्भावना पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय